रोजगार के लक्ष्य

975. श्री ईश दत्त यादव :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) उक्त लक्ष्यों को अब तक किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उदारीकरण की नीति से रोजगार के अवसरों के सृजन संबंधी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 5.6 प्रतिशत की अर्थ-व्यवस्था संवृद्धि दर के समनुरूप प्रतिवर्ष औसतन 8.5 मिलियन के अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 4.6 प्रतिशत की अर्थव्यवस्था संवृद्धि वार्षिक दर के समनुरूप 19.6 मिलियन अथवा औसतन 6.3 मिलियन प्रतिवर्ष अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने का आकलन लगाया गया है। रोजगार अवसरों के सृजन से संबंधित कार्यक्रमों पर उदारीकरण नीति का प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है।

मध्य प्रदेश के सांसदों द्वारा संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दिए गये प्रस्ताव

976. श्री राघवजी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन संसद-सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने "संसद सदस्यों द्वारा एक करोड़ रुपया व्यय किये जाने के संबंध में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि" के अन्तर्गत 31 जनवरी तक जिला मजिस्ट्रेटों के पास प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) उन संसद-सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं, जिनके प्रस्तावों पर संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित विकास कार्य आरंभ कर दिया गया है तथा प्रत्येक कार्य में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जायेगी;

(ग) शेष विकासात्मक कार्यों से संबंधित निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा ; और

(घ) इस विकासात्मक कार्य को प्रारंभ करने में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं तथा क्या मंत्रालय जिला मजिस्ट्रेट को इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के लिये निर्देश देगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Unemployment problem

977. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what concrete steps are being taken by Government to solve the problem of unemployment in India particularly in the rural areas of the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) what is the Central allocation for the same during the last three years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANGO): (a) and

(b) As stated in the Eighth Plan, in order to achieve a situation of near full-employment, additional employment must be generated in the process of growth itself, However, in the short run, to the extent the growth process will be pass certain sections of the society, it is necessary to provide supplementary employment and income to the poor through state intervention. Three major Centrally Sponsored programmes which are being implemented to increase the employment opportunities in the rural areas throughout the country are:—(i) Integrated Rural Development Programme (IRDP); (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY); and (iii) the Employment Assurance Scheme (EAS), While the IRDP is a sefl employment programme, the JRY and EAS are wage employment programmes. Intensified JRY or JRY (Second Stream) was introduced in 1993-94 in 120 backward districts of the country where there is a concentration of unemployment and under-employment. The EAS was launched on 2nd October, 1993 in identified backward blocks situated in the drought prone areas, desert areas, tribal areas and hill areas in which the Revamped Public Distribution System (RPDS) is in operation. In 1994-95, with the addition of 409 blocks covering new DPAP/DDP blocks and the Modified Area Development Approach (MADA) blocks having larger concentration of tribals, the EAS is presently being implemented in 2187 blocks in the country. The Prime Minister's Rozgar Yojana was launched on 2nd October, 1993 for providing self employment to educated unemployment Youth both in rural and urban areas. The scheme has been designed to provide employment by setting up of micro enterprises by the educated unemployed youth. It relates to the setting up of self-employment ventures through industry, service and business routes. Self Employment Scheme for Educated Enemployed Youth (SEEUY) which was in operation from 1983-84 to 1993-94 has been subsumed in the PMRY. Under PMRY Scheme capital subsidy is disbursed to the beneficiaries through banks by the Reserve Bank of India. Subsidy is provided at the rate of 15 per cent of the project cost subject to a ceiling of Rs 7,500 per entrepreneur. In addition some of the State Governments also have specific schemes in their own plans for creation of supplementary employment e.g. Employment Guarantee Scheme (EGS) in Maharashtra and Special Employment Programme in Gujarat.

(c) Does not arise.

(d) Central allocation during 1992-93, 1993-94 and 1994-95 are as follows:—

(Rs. in crores)

Programme	1992-93	1993-94	1994-95
(1)	(2)	(3)	(4)
IRDP	331.65	547.61	550.0
JRY (1st Stream)	2536.45	2546.00	2800.0
JRY (2nd Stream)	..	702·56	702.5
EAS	..	600.00 (Central outlay)	1200.0 (Centr outlay
		439·10 (Centnal Release	977.24 (Centr Release

£ Upto December 1994.